UMAYLAM मध्यम मार्ग नीति

Middle Way Approach

Peaceful conflict resolution for the 21st century

मध्यम मार्ग नीति

तिब्बती लोगों की असली स्वायत्त।

संश्रिप्त विवरण
कालक्रम
प्रश्न उत्तर

सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन
2017

UMAYLAM मध्यम मार्ग नीति
Middle Way Approach
Peaceful conflict resolution for the 21st century

संश्रिप्त विवरण
मध्यम मार्ग नीति

तिब्बत के लिए वाजिब स्वायत्ता

"तिब्बत मसले को हल करने के लिए स्वायत्तता के हर और प्रत्येक प्रावधान को, जिसकी गारंटी पीआरसी के संविधान और उसके राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता कानून में दी गई है, चीन सरकार को वाजिब तरीके से लागू करना चाहिए और समूची तिब्बती जनसंख्या को एक स्वायत्त प्रशासन के तहत लाया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अहिंसा ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए। ये मध्यम मार्ग नीति के अलंघनीय सिद्धांत हैं।"

मध्यम मार्ग नीति–प्रकृति और इतिहास

तिब्बती जनता की वास्तविक स्वायत्ता के लिए मध्यम मार्ग नीति (तिब्बती में जिसे 'उमेलम' कहते हैं) एक ऐसी नीति है जिसका बीजारोपण परमपावन दलाई लामा ने 1974 में किया था, इस प्रयास के तहत कि चीन सरकार को संवाद से जोड़ें और तिब्बत की विशिष्ट संस्कृति एवं पहचान की रक्षा के लिए एक शांतिपूर्ण रास्ता निकाला जा सके। यह एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनाई गई नीति थी जिसके लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) और तिब्बती जनता के द्वारा कई दशकों तक चर्चा की गई। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद प्रस्ताव है जिसमें कि यथास्थिति और स्वाधीनता के बीच का रास्ता अपनाया गया है–ऐसी नीति जिसमें तिब्बती जनता के प्रति चीन सरकार की मौजूदा दमनकारी और औपनिवेशिक नीतियों को स्पष्ट तरीके से खारिज किया गया है और चीन जनवादी गणतंत्र से अलग होने की बात भी नहीं की गई है।

आज तक दलाई लामा इस नीति को आगे बढ़ाने पर अडिग हैं, इसे तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों द्वारा सामना किए जा रहे गंभीर और तात्कालिक समस्याओं के हल के लिए एक यथार्थवादी एवं व्यावहारिक हल मानते हुए। इस नीति के तहत पहली उपलब्धि थी धर्मशाला और बीजिंग के बीच सीधा संवाद कायम होना, जब वर्ष 1979 में डेंग शियाओपिंग ने कहा कि तिब्बत की आज़ादी के अलावा बाकी हर मसले का समाधान बातचीत से किया जा सकता है। चीन की ज्यादा खुली नीति के वर्ष 1985 में एक बार फिर खत्म हो जाने से पहले तिब्बत में चार तथ्यान्वेषी दल भेजे गए।

अगले 17 वर्षों तक परमपावन दलाई लामा ने दुनिया भर के तमाम मंचों–अमेरिकी कांग्रेस और यूरोपीय संसद सहित–पर *मध्यम मार्ग नीति* को प्रस्तुत किया, इस उम्मीद में कि एक बार फिर चीनी नेतृत्व को बातचीत की मेज तक लाया जा सकेगा। वर्ष 2002 में फिर से वार्ता की शुरुआत हुई और अब तक कुल नौ दौर की वार्ता हो चुकी है। वर्ष 2008 में–जिस साल समूचे तिब्बत में अभूतपूर्व एवं व्यापक विरोध प्रदर्शन देखे गए– वार्ता के सातवें दौर के दौरान चीन सरकार ने तिब्बती नेतृत्व से यह कहा कि वह लिखित में दें कि उन्हें किस तरह की

स्वायत्तता चाहिए। वर्ष 2008 में ही हुए आठवें दौर की वार्ता में *तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता के लिए ज्ञापन* पेश किया गया। चीन सरकार ने इस ज्ञापन को लेकर कई तरह की चिंताएं और आपत्तियां जाहिर कीं। इनके समाधान के लिए जनवरी 2010 में नौवें और अंतिम दौर की वार्ता में तिब्बती नेतृत्व ने *तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता के लिए ज्ञापन के बारे में एक नोट* पेश किया। इस नोट में यह वर्णन किया गया कि आखिर किस तरह से तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता को चीन जनवादी गणतंत्र के ढांचे के भीतर ही संचालित किया जाएगाः उसके संविधान, उसकी प्रभुसत्ता एवं उसकी क्षेत्रीय अखंडता, उसकी तीन निष्ठाओं (1) और चीनी केंद्रीय सरकार (सीसीजी) की हायरार्की एवं अथॉरिटी का पालन करते हुए। नोट में चीन सरकार द्वारा उठाई गई कुछ विशिष्ट चिंताओं का समाधान किया गया हैः जैसे एकल प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रणाली, जन सुरक्षा, जनसंख्या के आव्रजन, भाषा और धर्म के लिए नियम–कायदों का स्वरूप आदि। इस नोट में यह प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई है कि ज्ञापन में सीसीजी द्वारा प्रकट किए गए "अपनी स्थिति और विभिन्न मामलों पर इरादों को लेकर संदेहों और चिंताओं" को दूर करने के लिए परमपावन दलाई लामा एक औपचारिक बयान जारी करने को तैयार हैं।

तिब्बती नेतृत्व तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता हासिल करने के लिए *मध्यम मार्ग नीति* पर चलने की अपनी प्रतिबद्धता और परमपावन दलाई लामा के दूतों एवं चीनी नेतृत्व के बीच संवाद के द्वारा एक स्थायी समाधान को लेकर अटल बना हुआ है।
(मध्यम मार्ग नीति के ज्यादा विस्तृत इतिहास की जानकारी के लिए कृपया अलग से दिए घटनाक्रम को देखें)

मध्यम मार्ग नीति के द्वारा तिब्बती जनता क्या चाहती है?

इसके द्वारा तिब्बती स्वशासन का ऐसा तरीका चाहते हैं जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और इससे चीन जनवादी गणतंत्र की एकता और स्थिरता को भी कोई चुनौती नहीं मिलेगी। तिब्बती स्वायत्तता का ऐसा स्वरूप चाहते हैं जिसमें तिब्बती जनता अपने रीति–रिवाजों एवं मूल्यों, भाषा, जीवन पद्धति और भूगोल को साझा कर सकें। उन्हें एकल प्रशासनिक ईकाई में शामिल करना शासन का ज्यादा प्रभावी और सक्षम तरीका होगा, बजाय मौजूदा प्रणाली के जिसमें तिब्बतियों को तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) और पड़ोसी चीनी बहुल प्रांतों (क्विंघई, सिचुआन, गांसू और यून्नान) में बांट दिया गया है। चीनी प्रशासन का दावा है कि तिब्बती नेतृत्व का इरादा तिब्बती इलाकों से 'सभी चीनियों' को बाहर निकालने का है। सच तो यह है कि इस ज्ञापन में साफ तौर से यह कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगाः "गैर तिब्बतियों को बाहर निकालने का हमारा इरादा नहीं है। हमारी चिंता यह है कि मुख्यतः हान लोगों और कुछ दूसरे राष्ट्रीयताओं के लोगों की भी बहुत से तिब्बती इलाकों में बड़े पैमाने पर बसने की घटना बढ़ रही है जिससे उन इलाकों में मूल तिब्बती जनसंख्या हाशिये पर जा रही है।" इस ज्ञापन में आह्वान किया गया है कि तिब्बती इलाकों में तिब्बतियों की बहुलता बनाए रखी जाए ताकि विशिष्ट तिब्बती पहचान का सरंक्षण हो सके और उसे बढ़ावा मिल सके। चीन जनवादी गणतंत्र में तिब्बतियों की जनसंख्या करीब 62 लाख है (स्रोतः पीआरसी की छठी राष्ट्रीय जनगणना) जो कि चीन की कुल जनसंख्या का महज 0.47 फीसदी

ही है।

एक तिब्बती क्षेत्रीय प्रशासन तिब्बतियों की 11 बुनियादी जरूरतों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा, जो इस प्रकार हैं:

भाषा, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, आर्थिक विकास एवं व्यापार, जन स्वास्थ्य, जन सुरक्षा, जनसंख्या आव्रजन के बारे में नियम–कायदे और दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक विनिमय।
यह राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता कानून और चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान दोनों के अनुरूप है।

---

1. केंद्र सरकार ने जिन 'तीन निष्ठाओं' के पालन की शर्त रखी है वह हैं: (1) चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व, (2) चीनी विशिष्टताओं वाला समाजवाद और (3) क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्त व्यवस्था।

परमपावन दलाई लामा की भूमिका

वर्ष 2011 में परमपावन दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को चुने हुए तिब्बती नेतृत्व को सौंप दिया–केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) जिसका नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता "सिक्योंग" कर रहे हैं।

परमपावन तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाले तिब्बतियों के सबसे पूज्यनीय अगुआ हैं। तिब्बत जनता को उनके नेतृत्व से यह उम्मीदें हैं और उन्हें सबसे ज्यादा उन पर ही भरोसा है कि वह तिब्बत के भीतर के हालात के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। ज्ञापन में जैसा कि साफ तौर से कहा गया है, परमपावन दलाई लामा ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि वह तिब्बत में कोई भी राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेंगे। हालांकि, दलाई लामा के रूप में वह इस बात के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं कि मौजूदा गतिरोध का कोई समाधान निकालने के लिए जिस तरह के सहयोग की भी जरूरत होगी वह देंगे और *मध्यम मार्ग नीति* की प्रबल और अटल रूप से वकालत करते रहेंगे।

मध्यम मार्ग नीति को व्यापक समर्थन

तिब्बती नेतृत्व का यह मानना है कि *मध्यम मार्ग नीति* तिब्बत की मौजूदा अत्यावश्यक हालात का सबसे व्यवहार्य हल है। यह ऐसा रवैया है जिसे सबसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी हासिल हुआ है। कई राष्ट्रीय सरकारों ने आधिकारिक रूप से परमपावन दलाई लामा के दूतों और नए चीनी नेतृत्व के प्रतिनिधियों के बीच संवाद के लिए अपना समर्थन दिया है। इनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। अकेले पिछले दो वर्षों में ही संवाद को समर्थन देने के बारे में प्रस्ताव, संकल्प और बयान अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और लक्जमबर्ग जैसी कई संसदों में पारित हुए हैं।

मध्यम मार्ग नीति को हर साल चीनी समुदाय में भी समर्थन बढ़ता जा रहा है। चीन के कई सबसे सम्मानित बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने इस नीति का समर्थन किया है। इनमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैदी लिउ शियाओबो भी शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2008 में जारी उस खुले पत्र पर भी दस्तखत किया था जिसमें परमपावन दलाई लामा के शांति पहल को समर्थन दिया गया था। इसके बाद से चीनी विद्वानों और लेखकों द्वारा तिब्बत मसले को हल करने के लिए संवाद का समर्थन करने वाले 1,000 से ज्यादा लेख एवं विचार पेश किए गए हैं। इनमें बीजिंग के एक कानूनी एनजीओ, दि गोंगमेंग कॉन्सटिट्यूशनल इनीशिएटिव की एक रिपोर्ट शामिल है जिसमें तिब्बती जनता की समस्याओं का वर्णन करते हुए नीतियों की समीक्षा करने का आह्वान किया गया है। वर्ष 2012 में 15 देशों में सक्रिय 82 चीनी एनजीओ ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, विभिन्न संसदों और सरकारों को एक याचिका भेजकर उनसे यह आग्रह किया कि "चीन सरकार से निवेदन करें कि वह जितनी जल्दी संभव हो वार्ता शुरू करे।"

मध्यम मार्ग नीति का समर्थन करने वाले अन्य चीनी बुद्धिजीवियों में प्रख्यात लेखक वांग लिशियोंग, चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी से जुड़े और सांविधानिक विशेषज्ञ झांग बोशु, सिचुआन लिटररी पीरियॉडिकल के रान यनफेई, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और बीजिंग में रहने वाले कानूनी जानकार यू हाओछेंग, चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी के पूर्व अर्थशास्त्री सु शाओझी और कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव झाओ जियांग के करीबी सहयोगी यान जियाकी शामिल हैं।

मध्यम मार्ग नीति को प्रभावी बनाने के लिए वार्ता का आह्वान करने वाले वैश्विक नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त नवी पिल्लई, विदेशी मामलों/सुरक्षा नीति पर यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष लेडी कैथरीन एश्टन, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड और ताइवानी राष्ट्रपति मा यिंग जेआयू शामिल रहे हैं।

राष्ट्रपति बराक ओबामा की परमपावन दलाई लामा से 16 जुलाई 2011 और फिर 21 फरवरी 2014 को मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने "दलाई लामा की अहिंसा और मध्यम मार्ग नीति के अनुसरण में चीन के साथ संवाद की प्रतिबद्धता" की सराहना की और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि, "लंबे समय से जारी मतभेदों को दूर करने के लिए सीधे संवाद कायम करें।" व्हाइट हाउस ने कहा, "ऐसा संवाद जिसका कोइ नतीजा निकले चीन और तिब्बतियों, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा।"

मध्यम मार्ग नीति का बहुत से नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित हस्तियों ने भी समर्थन किया है जिनमें दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टुटु, अमेरिका के एली विजेल, अमेरिका के जोडी विलियम्स, लाइबेरिया के लेमाह गोवी, पोलैंड के लेक वालेसा, ईरान के शिरीन ईबादी,

ग्वाटेमाला के रिगोबर्टा मेंछु, ईस्ट टिमोर के जोस रामोस होर्ता, अर्जेंटीना के अडोल्फो पेरेज एसक्विवेल, आयरलैंड के मैरीड कॉरिगन मैग्वायर और ब्रिटेन के बेट्टी विलियम्स शामिल हैं। चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ को वर्ष 2012 में लिखे खुले पत्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं ने लिखा थाः "तिब्बत के लोगों की आकांक्षा को सुना जाना चाहिए। वे लंबे समय से सार्थक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने बातचीत और दोस्ताना मदद का रास्ता अख्तियार किया है। चीन सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और कोई अहिंसक समाधान निकालना चाहिए। इस तरह के समाधान की पेशकश हमारे मित्र और भाई परमपावन दलाई लामा ने की है जिन्होंने कभी भी अलग होने की बात नहीं की है और हमेशा एक शांतिपूर्ण रास्ता चुना है। हम चीन सरकार से यह प्रबल आग्रह करते हैं कि एक सार्थक वार्ता के लिए उनके द्वारा दिए जा रहे मौके का वह फायदा उठाए। एक बार इस संवाद माध्यम के बन जाने के बाद इसे खुला, सक्रिय और उत्पादक बनाए रखना चाहिए। इसके द्वारा उन मसलों का समाधान होना चाहिए जो मौजूदा तनाव की मूल हैं और इसमें तिब्बती जनता की गरिमा तथा चीन की अखंडता का सम्मान होना चाहिए।"

मध्यम मार्ग नीति का समर्थन करने वाले तिब्बत के भीतर के नेताओं में स्वर्गीय पंचेन लामा शामिल रहे हैं जिन्होंने खुलकर इस नीति का समर्थन किया था। तिब्बत सरकार में पूर्व मंत्री स्वर्गीय गापो गवांग जिग्मे ने चीन सरकार से आग्रह किया था कि वह अपने 17 सूत्रीय समझौते (1) के अनुसार तिब्बत में क्षेत्रीय स्वायत्तता को लागू करे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ तिब्बती अधिकारी स्वर्गीय बाबा फुंत्सोक वांगयाल ने कहा था, "तिब्बत के लिए स्वतंत्रता की जगह सिर्फ एक सार्थक स्वायत्तता हासिल करने की दलाई लामा की मध्यम मार्ग नीति, मौजूदा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, उस महान जिम्मेदारी को अभिव्यक्त करता है कि वह तिब्बत और कुल मिलाकर तिब्बतियों के बुनियादी हितों, भविष्य और नियति को लेकर कितने गंभीर हैं। इससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने दोनों पक्षों से जुड़े मसलों को समझने की महती जिम्मेदारी ली है और बदलती परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा, यह सोच वास्तविकता और दूरदृष्टि पर आधारित है।"

वरिष्ठ तिब्बती कम्युनिस्ट नेता एवं बीजिंग के तिब्बतोलॉजी रिसर्च सेंटर के पूर्व निदेशक दोरजी सेतेन, वरिष्ठ तिब्बती कम्युनिस्ट नेता सांगये येशी (तियान बाओ), ल्हासा के तिब्बत विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफसर टाशी सेरिंग और गांजी (तिब्बती में कार्डजे) प्रशासनिक क्षेत्र के देरगे काउंटी के वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता यांगलिंग दोरजी जैसे कई तिब्बती नेताओं ने सभी तिब्बती जनता को एक प्रशासनिक ईकाई के तहत रखने के विचार का समर्थन किया है।

आगे का रास्ता

तिब्बती प्रशासन चीनी समुदाय और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन चाहता है ताकि चीन सरकार को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि वह मेल–मिलाप की भावना और इस विचार के साथ कि वाजिब स्वायत्तता से दोनों पक्षों को कई फायदे होंगे, वार्ता फिर से शुरू करे। तिब्बती नेतृत्व का यह मानना है कि चीन की केंद्रीय सरकार लंबे समय तक

अपने इस पक्ष का बचाव नहीं कर सकती कि तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बती मौजूदा चीनी नीतियों से संतुष्ट हैं। इसलिए तिब्बतियों को अपने मामलों में निर्णय लेने का वाजिब हक देना चाहिए ताकि वह सौहार्द् के साथ रह सकें। मध्यम मार्ग नीति के द्वारा चीन जनवादी गणतंत्र अपनी वैधानिक मौजूदगी रखते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को सुनिश्चित कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इससे चीन दुनिया भर के लोगों के दिल–दिमाग में अपनी सकारात्मक छवि को बढ़ा सकता है, साथ ही वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा भी कर सकता है।

---

1. *सैन्य आक्रमण के भय के बीच 1951 में तिब्बत सरकार को एक समझौते पर दस्तखत करने को मजबूर किया गया था, लेकिन जब चीन अपनी प्रतिबद्धता पर कायम नहीं रहा तो 1959 में परमपावन दलाई लामा ने इस समझौते को खारिज कर दिया।*

घटनाक्रम

मध्यम मार्ग नीति का कालक्रम

इस कालक्रम को बहुत व्यापक बनाने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि इसमें *मध्यम मार्ग नीति* के इतिहास के मुख्य बिंदुओं को दिया गया है।

1949 चीन की जनमुक्ति सेना का हमला और उसने तिब्बत पर नियंत्रण हासिल करना शुरू किया।

1951–1959 वर्ष 1951 में चीन सरकार ने तिब्बती प्रतिनिधियों को "तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के उपायों के लिए एक 17 बिंदुओं वाले समझौते" पर दस्तखत के लिए मजबूर किया। हालांकि, बाद में चीन सरकार ने ही इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया और इसका पालन करने में विफल रही।

1959 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में प्रतिरोध शुरू होने लगा, मार्च 1959 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एक राष्ट्रीय जनक्रांति की शुरुआत हो गई। चीनी सुरक्षा बलों ने इस जनक्रांति को कुचल दिया जिसके तहत सात महीने के भीतर करीब 87,000 तिब्बतियों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। इन सुरक्षा बलों से बचते हुए करीब 80,000 तिब्बती परमपावन दलाई लामा के साथ हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए भारत, नेपाल और भूटान में निर्वासन में रहने चले गए।

1959–1974 भारत सरकार के सहयोग से दलाई लामा ने उत्तर भारत में निर्वासन का केंद्र बनाया। वह पहले मसूरी में और इसके बाद धर्मशाला में बसे जहां केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) की स्थापना की गई है। अगले वर्षों में परमपावन दलाई लामा और सीटीए के सहयोग एवं मार्गदर्शन के साथ निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों ने खुद को दुनिया भर में एक निर्वासित समुदाय के रूप में स्थापित किया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तिब्बत के मसले पर 1959, 1961 और 1965 में तीन प्रस्ताव स्वीकार किए।

1974 करीब 15 साल तक निर्वासन में रहने और तिब्बत के भीतर के हालात की गंभीरता पर विचार करते हुए तथा पीड़ित तिब्बतियों के उत्थान की जरूरत को देखते हुए परमपावन ने तिब्बत मसले को हल करने के लिए दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद प्रस्ताव का बीजारोपण किया। उन्होंने कशाग (सीटीए/तिब्बती मंत्रिमंडल के सदस्यों), निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों और तिब्बत के भरोसेमंद मित्रों के साथ लगातार चर्चाएं कीं। चीन जनवादी गणतंत्र से अलग होने की जगह स्वायत्तता की एक नीति– *"मध्यम मार्ग"* पर आगे बढ़ने का एक

आंतरिक निर्णय लिया गया। इस नीति को *मध्यम मार्ग नीति* (तिब्बती में "उमेलम") के रूप में जाना गया।

1979 चीन के सर्वोपरि नेता देंग शियोपिंग ने कहा कि तिब्बत की स्वतंत्रता के अलावा तिब्बत के बारे में बाकी हर मसले पर चर्चा की जा सकती है और उसे वार्ता के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने परमपावन से बातचीत की पेशकश की। तब तक *मध्यम मार्ग नीति* तो विकसित हो ही चुकी थी, देंग शियोपिंग को सकारात्मक जवाब भेजा गया, इससे धर्मशाला और बीजिंग के बीच संपर्क और चर्चाओं के लंबे दौर की शुरुआत हुई।

1979–1985 चीन ने तिब्बत में चार तथ्यान्वेषी दल भेजा जाना स्वीकार किया जो अगस्त 1979, मई 1980, जून 1980 और जून 1985 में गए। इन प्रतिनिधिमंडलों का स्थानीय तिब्बतियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इन दलों के सदस्यों ने यू–सांग के ल्हासा, शिगास्ते, ल्होखा, कोंगपो, साक्य, निंगत्री, ल्हुंत्से, सोना, सेथांग, ग्यांगत्से, छोखोरग्याल, सांगाछोलिंग, यारतोक और नाकर्तसे, आमदो के कानल्हो, सिलिंग, गोलोक, माल्हो, नाबा और जोएगे, खम के नांगछू, चामदो, देगे, कार्से, न्यारोंग, ग्यालथांग और मारखम जैसे तिब्बत के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। वर्ष 1982 और 1984 में चीनी नेता बीजिंग में वार्ता के लिए धर्मशाल से आए तथ्यान्वेषी प्रतिनिधिमंडल से मिले। पर 1985 के तथ्यान्वेषी प्रतिनिधिमंडल के बाद चीन ने आगे किसी और दल के आने से मना कर दिया और इसके लिए कोई वजह भी नहीं बताई गई।

1987 परमपावन दलाई लामा ने अमेरिकी कांग्रेस के मानवाधिकार गुट को संबोधित किया और उनके सामने तिब्बत के लिए एक पांच बिंदुओं वाली समझौता योजना पेश की, जिसमें *मध्यम मार्ग नीति* के आधार पर चीन सरकार के साथ जल्द से जल्द बातचीत करने का प्रस्ताव था।

1987–1989 वर्ष 1987 में ल्हासा में बड़े पैमाने पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जिसका चीनी सुरक्षा बलों ने बर्बरता से दमन किया। इसके बाद दमन और गिरफ्तारियों की नई लहर शुरू हो गई। चीन ने मार्च 1989 में ल्हासा में सैनिक शासन की घोषणा कर दी।

1988 इन विरोध प्रदर्शनों के बीच परमपावन दलाई लामा ने स्ट्रासबर्ग प्रस्ताव पेश किए, जिसमें पांच बिंदुओं वाली समझौता योजना का वर्णन किया गया था। सितंबर में चीन ने तिब्बतियों से बातचीत की इच्छा जताई और कहा कि इस बातचीत के लिए दलाई लामा अपने पसंद की तिथि और स्थान का चुनाव कर सकते हैं। तिब्बतियों के साथ बातचीत के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए धर्मशाला ने बातचीत के लिए एक छह सदस्यीय दल की घोषणा की। पर, बातचीत शुरू होने से पहले ही चीन सरकार अपने कठोर रवैये पर वापस लौट गई और उसने कहा कि स्ट्रासबर्ग प्रस्तावों को वार्ता का आधार नहीं बनाया जा

सकता।

1989 सहिष्णुता और परस्पर सम्मान के रवैये के आधार पर तिब्बत मसले के एक शांतिपूर्ण समाधान का वकालत करने के लिए परमपावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

1992 चीन सरकार से किसी तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से परमपावन दलाई लामा ने स्ट्रासबर्ग प्रस्तावों को अवैध घोषित कर दिया।

1993 परमपावन दलाई लामा द्वारा कई राजनयिक प्रयासों पर चीन की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से चीन सरकार के साथ बना 14 साल का औपचारिक संपर्क खत्म हो गया। अगले साल यानि 1994 में बीजिंग ने तीसरे "तिब्बत कार्य मंच" का आयोजन किया, जिसमें उसने तिब्बत पर कठोर नीति को अपनाया। यह पहले के मंचों पर अपनाए गए ज्यादा खुले रवैये से बिल्कुल विपरीत बात थी।

1994 बीजिंग के रवैये में बदलाव को देखते हुए परमपावन दलाई लामा ने प्रस्ताव रखा कि चीन के साथ भविष्य में किस तरह का व्यवहार हो और तिब्बती स्वतंत्रता संघर्ष के तरीके पर नए सिरे से विचार के लिए तिब्बती समुदाय के बीच एक जनमत संग्रह कराया जाए।

1997 सितंबर 1997 में निर्वासित तिब्बती संसद (टीपीआइई) ने एकमत से एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि भविष्य में चीन–तिब्बत मसलों के बारे में कोई भी निर्णय परमपावन को ही लेना चाहिए। इससे इस बात की झलक मिली कि तिब्बती जनता परमपावन दलाई लामा में अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में अगाध भरोसा रखती है। निर्वासित तिब्बती संसद ने यह प्रस्ताव भी पारित किया कि परमपावन दलाई लामा जो भी निर्णय लेंगे उसे समूची तिब्बती जनता इसी तरह से मानेगी जैसे कि इसके लिए तिब्बती समुदाय में जनमत संग्रह किया गया हो।

1998 मार्च, 1998 में धर्मशाला में एक जन संबोधन में परमपावन दलाई लामा ने पिछले साल की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुद में भरोसा जताने और अपने से इतनी उम्मीद के लिए तिब्बत की जनता के प्रति आभार जताया और *मध्यम मार्ग नीति* के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

2001 परमपावन दलाई लामा ने यूरोपीय संसद के समापन सत्र को संबोधित करते यह आग्रह किया कि वार्ता फिर से शुरू की जानी चाहिए।

2002 चीन के साथ वार्ता फिर से शुरू हुई जो मध्यम मार्ग नीति के आधार पर हुई नौ "दौर की वार्ताओं" में से पहली थी। परमपावन दलाई लामा के दूतों और चीन

सरकार के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की वार्ता सितंबर 2002 में बीजिंग में शुरू हुई। इसके बाद दूसरे दौर की वार्ता मई–जून 2003 में बीजिंग में, तीसरे दौर की वार्ता सितंबर 2004 में बीजिंग में, चौथे दौर की वार्ता जून–जुलाई 2005 में बर्न, स्विट्जरलैंड में, पांचवें दौर की वार्ता फरवरी 2006 में चीन के गुईलिन सिटी में, छठे दौर की वार्ता जून–जुलाई 2007 में शंघाई एवं नानजिंग में, मई 2008 में शेनझेन में एक अनौपचारिक मुलाकात, सातवें दौर की वार्ता जून–जुलाई 2008 में बीजिंग में, आठवें दौर की वार्ता अक्टूबर–नवंबर 2008 में बीजिंग में और नौवें दौर की वार्ता जनवरी–फरवरी 2010 में हुनान प्रांत और बीजिंग में हुई।

2008 वर्ष 2008 की पहली छमाही में समूचे तिब्बत में अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जुलाई 2008 में चीन सरकार के साथ हो रहे सातवें दौर की वार्ता में चीनी वार्ताकारों ने तिब्बती नेतृत्व से कहा कि वे लिखित रूप से दें कि उन्हें किस तरह की स्वायत्तता चाहिए। इसके बाद उसी साल अक्टूबर–नवंबर के दौरान हुई आठवें दौर की वार्ता में *तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता पर ज्ञापन* पेश किया गया। इस ज्ञापन–जो कि चीनी संविधान के ढांचे के तहत ही लिखा गया था–में कई चीजों को परिभाषित किया गया था जैसे "चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर तिब्बती राष्ट्रीयता के लिए एकल प्रशासन को लागू करने", "स्वायत्तता की प्रकृति और ढांचा" और "तिब्बतियों के लिए 11 बुनियादी जरूरतें।" चीनी नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इस झूठे दावे के आधार पर कि ज्ञापन में 'वृहद तिब्बत', 'स्वायत्तता की ऊंची मात्रा', 'छद्म स्वतंत्रता' और 'गुप्त तरीके से स्वतंत्रता' जैसे संदर्भ शामिल हैं। इन सब संदर्भों को चीनी संविधान और उसके क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता कानून के खिलाफ माना जाता है।

2009 तिब्बत में चीन सरकार के लगातार जारी कब्जे और राजनीतिक दमन, धार्मिक उत्पीड़न, सांस्कृतिक विलोपन और वहां की जनता के आर्थिक हाशियाकरण तथा वहां की भूमि के पर्यावरणीय क्षरण के विरोध में तिब्बतियों ने आत्मदाह करना शुरू कर दिया। अपनी जान देने का प्रयास करने समय आत्मदाह करने वाले लोग लगातार परमपावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी और तिब्बतियों को आज़ादी देने के नारे लगाते हैं।

2010 ज्ञापन पर जताई गई चीन सरकार की चिंताओं और आपत्तियों का समाधान करने के लिए 9वें दौर की वार्ता के दौरान *तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता पर ज्ञापन पर एक टिप्पणी* पेश की गई। इस टिप्पणी में यह वर्णित किया गया कि किस तरह से तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता को चीन जनवादी गणतंत्र के ढांचेः उसके संविधान, क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता, उसकी 'तीन निष्ठाओं' (1) और चीन की केंद्रीय सरकार (सीसीजी) के हायरार्की और अथॉरिटी के भीतर ही संचालित किया जाएगा। एकल प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, जन सुरक्षा, जनसंख्या के आव्रजन पर नियंत्रण,

भाषा और धर्म के बारे में चीन सरकार द्वारा जताई गई कुछ विशिष्ट चिंताओं का समाधान भी इस नोट में किया गया। हालांकि, चीन सरकार ने एक बार फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

2011 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के जुलाई 2011 और फिर 21 फरवरी, 2014 को परमपावन दलाई लामा से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने "मध्यम मार्ग नीति के अनुसरण में अहिंसा और चीन के साथ संवाद कायम करने की दलाई की प्रतिबद्धता" की तारीफ की और संबंधित पक्षों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे "लंबे समय से जारी मतभेदों को दूर करने के लिए सीधा संवाद कायम करें" और व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि "संवाद से जो नतीजा निकलेगा वह चीन और तिब्बतियों, दोनों के लिए सकारात्मक होगा।" सिक्योंग डॉ.लोबसांग सांगे के नेतृत्व में तिब्बती नेतृत्व ने मध्यम मार्ग नीति के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और साफ तौर से कहा कि परमपावन के दूतों और नए चीनी नेतृत्व के बीच वार्ता ही आगे बढ़ने के लिए एकमात्र मार्ग है।

आज 17 अप्रैल, 2014 तक के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2009 से अब तक कम से कम 130 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। परमपावन दलाई लामा और चीनी नेतृत्व के बीच वार्ता ठप पड़ी हुई है, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कई सरकारों ने वार्ता प्रक्रिया को आगे के लिए एक व्यवहार्य और वाजिब रास्ता माना है। तिब्बत के भीतर लगातार बिगड़ते हालात और 130 से ज्यादा लोगों के आत्मदाह कर लेने के बावजूद *मध्यम मार्ग नीति* के प्रति तिब्बती जनता की प्रतिबद्धता अटल है। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय समर्थन की वजह से इस नीति के प्रति उनका भरोसा और बढ़ रहा है, इसे समर्थन देने वालों में बहुत से चीनी लोग भी हैं जो शांति और न्याय में भरोसा करते हैं।

---

1 केंद्र सरकार ने जिन 'तीन निष्ठाओं' के पालन की शर्त रखी है वह हैं: (1) चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व, (2) चीनी विशिष्टताओं वाला समाजवाद और (3) क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्त व्यवस्था।

तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता हासिल करने के लिए मध्यम मार्ग नीति के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मध्यम मार्ग नीति क्या है?

तिब्बती जनता को वाजिब स्वायत्तता देने के लिए *मध्यम मार्ग नीति* (तिब्बती में "उमेलम") एक ऐसी नीति है जिसका बीजारोपण परमपावन ने वर्ष 1974 में किया था, इस प्रयास के तहत कि चीन सरकार को संवाद से जोड़ा जा सके और तिब्बत की विशिष्ट संस्कृति एवं पहचान की रक्षा के लिए एक शांतिपूर्ण रास्ता तलाशा जा सके। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद प्रस्ताव है जिसमें कि यथास्थिति और स्वाधीनता के बीच का रास्ता अपनाया गया है–ऐसी नीति जिसमें तिब्बती जनता के प्रति चीन सरकार की मौजूदा दमनकारी और औपनिवेशिक नीतियों को स्पष्ट तरीके से खारिज किया गया है और चीन जनवादी गणतंत्र से अलग होने की बात भी नहीं की गई है। यह एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनाई गई नीति थी जिसके लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) और तिब्बती जनता के द्वारा कई दशकों तक चर्चा की गई।

यह एक व्यावहारिक स्थिति है जिससे संबंधित पक्षों का व्यापक हित सधता है: तिब्बतियों के लिए उनकी पहचान और गरिमा की रक्षा एवं संरक्षण और चीनियों के लिए उनकी मातृभूमि की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता। इसकी वजह से ही 1979 में पहली बार परमपावन दलाई लामा के दूतों और चीन सरकार के बीच सीधा संवाद संभव हो सका, निर्वासित तिब्बती नेतृत्व के चार तथ्यान्वेषी प्रतिनिधिमंडल गए, जिन्होंने तिब्बत के भीतर की गहन यात्रा की और 1982 तथा 1984 में अन्वेषी वार्ताएं हुईं। वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2010 तक परमपावन दलाई लामा के दूतों और चीनी नेतृत्व के बीच नौ दौर की औपचारिक वार्ताएं और एक अनौपचारिक बैठक हुई।

2. स्वायत्तता की मांग क्यो की जा रही है?

तिब्बती नेतृत्व का मानना है कि वाजिब स्वायत्तता तिब्बत और चीन दोनों के लिए व्यावहारिक और फायदेमंद समाधान है। आज की परस्पर निर्भर दुनिया में कोई भी देश दूसरों पर निर्भर रहे बिना अलग–थलग नहीं रह सकता। बहुत से देश यूरोपीय संघ जैसे महासंघों में शामिल होकर अपने कुछ व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग कर रहे हैं।

3. तिब्बत में वाजिब स्वायत्तता का कौन–सा स्वरूप होगा?
तिब्बती स्वशासन का एक ऐसा स्वरूप चाहते हैं जिसमें उन्हें अपने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की इजाजत हो, लेकिन इससे चीन जनवादी गणतंत्र की एकता और स्थिरता को

कोई चुनौती न हो। तिब्बती लोग स्वायत्तता का ऐसा स्वरूप चाहते हैं जिसमें वे रीति–रिवाजों, मूल्यों, भाषा, जीवन पद्धति और भूगोल को साझा कर सकें। तिब्बत को एकल प्रशासनिक प्रणाली के तहत लाना शासन के मौजूदा स्वरूप से ज्यादा सक्षम और प्रभावी साबित होगा। मौजूदा शासन प्रणाली में तो तिब्बतियों को चार स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) और पड़ोसी प्रांतों क्विंघई, सिचुआन, गांसू तथा यून्नान में बांट दिया गया है, जहां चीनी लोग बहुमत में हैं।

चीनी प्रशासन का दावा है कि तिब्बती नेतृत्व का इरादा तिब्बती इलाकों से "सभी चीनियों" को बाहर कर देने का है। वास्तव में *तिब्बती जनता को वास्तविक स्वायत्तता के लिए ज्ञापन* से साफ तौर से यह पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है: तिब्बती इलाकों में वर्षों से रह रहे गैर तिब्बती वहीं बने रहेंगे। हमारी चिंता यह है कि तिब्बती इलाकों में मुख्यतः हान और कुछ दूसरी राष्ट्रीयताओं के लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही बढ़ी है जिससे मूल तिब्बती जनसंख्या हाशिये पर जा रही है।" इस ज्ञापन में आह्वान किया गया है कि तिब्बत की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि तिब्बती इलाकों में तिब्बतियों की बहुलता हो। चीन जनवादी गणतंत्र में तिब्बती जनसंख्या महज 62 लाख ही है (स्रोतः पीआरसी की छठी राष्ट्रीय जनगणना) जो कि चीन की कुल जनसंख्या का करीब 0.47 फीसदी ही होता है।

एक तिब्बती क्षेत्रीय प्रशासन तिब्बतियों की 11 बुनियादी जरूरतों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा, जो इस प्रकार हैं:

भाषा, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, आर्थिक विकास एवं व्यापार, जन स्वास्थ्य, जन सुरक्षा, जनसंख्या आव्रजन के बारे में नियम–कायदे और दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक विनिमय।

यह राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता कानून और चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान दोनों के अनुरूप है।

4. मध्यम मार्ग नीति को क्या तिब्बती जनता का व्यापक समर्थन हासिल है? तिब्बती जनता ने इसके प्रति अपना समर्थन किस तरह से जताया है?

जी हां, मध्यम मार्ग नीति को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की आधिकारिक नीति के रूप में स्वीकार किया गया था और इसके लिए वर्ष 1988 से 2010 के बीच लगातार कई बैठकों एवं जनमत सर्वेक्षणों में बहुसंख्यक जनता की मंजूरी ली गई है। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा किया गया है जिसके लिए न केवल निर्वासित तिब्बती संसद और कशाग से ही परामर्श लिया गया है, बल्कि तिब्बती जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की भी सीधी राय ली गई है। वर्ष 1997 में हुए एक जनमत सर्वेक्षण में 64 फीसदी लोगों ने कहा कि इसके लिए जनमत संग्रह कराने की जरूरत नहीं है और इस मामले में दलाई लामा जिस भी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं वे उनका समर्थन करेंगे। जनमत सर्वेक्षण के नतीजे के

आधार पर निर्वासित तिब्बती संसद ने 18 सितंबर 1997 को मध्यम मार्ग नीति के समर्थन में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया।

इसी प्रकार नवंबर 2008 में पहली बार हुए छह दिन की विशेष आम सभा में 80 फीसदी से ज्यादा लोगों ने मध्यम मार्ग नीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया। अंततः मार्च 2010 में निर्वासित तिब्बती संसद ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात में अपना भरोसा दोहराया कि 18 सितंबर 1997 को संसद द्वारा सर्वसम्मत से पारित प्रस्ताव के अनुसरण में तिब्बत मसले को हल करने के लिए परमपावन दलाई लामा अपनी समझ का इस्तेमाल करें। इस तरह मध्यम मार्ग नीति को तिब्बतियों के भारी बहुमत का समर्थन हासिल है।

5. तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों ने मध्यम मार्ग नीति के प्रति अपना समर्थन किस तरह से व्यक्त किया है?

वैसे तो तिब्बत के भीतर से लोगों का मत जुटा पाना असंभव है, लेकिन परमपावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके विचारों को समाहित करने का हर संभव प्रयास किया है। उदाहरण के लिए तिब्बत से नए आने वाले तिब्बतियों को जून 1988 में आयोजित एक विशेष राजनीतिक बैठक में हिस्सेदारी लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1995–96 में जनमत संग्रह के लिए हुए एक जनमत सर्वेक्षण में तिब्बत के भीतर के लोगों की राय भी जुटाई गई। नवंबर 2008 में आयोजित पहली विशेष आमसभा में तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों से लिखित और मौखिक सुझाव भेजने का निवेदन किया गया। इनमें बहुमत मध्यम मार्ग नीति के पक्ष में था।

इसके अलावा मध्यम मार्ग नीति को तिब्बत के भीतर के कई ऊंचे दर्जे के तिब्बती नेताओं और बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला है जिनमें स्वर्गीय पंचेन लामा भी शामिल रहे जिन्होंने मध्यम मार्ग नीति का खुलकर समर्थन किया था। इसके अलावा गापो गवां जिग्मे, बाबा फुंत्सोक वांगयाल, दोरजी सेतेन, सांगये येशी (तियान बाओ), टाशी सेरिंग और यांगलिंग दोरजी जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस नीति का समर्थन किया है।

6. मध्यम मार्ग नीति क्या सिर्फ सांस्कृतिक स्वायत्तता की वकालत करती है?

जी नहीं, मध्यम मार्ग नीति स्वशासन की वकालत करती है। यह सिर्फ सांस्कृतिक स्वायत्तता तक सीमित नहीं है। *तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता के लिए ज्ञापन* में "तिब्बती जनता की बुनियादी जरूरतें" शीर्षक वाले खंड के तहत स्वशासन के 11 क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है, जो चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर तिब्बती राष्ट्रीयता के लिए एकल प्रशासन को अमल में लाकर हो सकता है।

"तिब्बतियों की बुनियादी जरूरतें" इस प्रकार हैं:

1. भाषा
2. संस्कृति
3. धर्म
4. शिक्षा
5. पर्यावरण संरक्षण
6. प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल
7. आर्थिक विकास एवं व्यापार
8. जन स्वास्थ्य
9. सार्वजनिक सुरक्षा
10. जनसंख्या आव्रजन पर नियंत्रण
11. दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक आदान–प्रदान

7. *तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता* के तहत मौजूदा समय के तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) और पड़ोसी तिब्बती बाशिंदों के इलाकों में रहने वाले गैर तिब्बतियों का क्या भविष्य होगा?

जैसा कि *तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता के लिए ज्ञापन पर नोट* में कहा गया है: "हमारा इरादा उन गैर तिब्बतियों को बाहर निकालने का नहीं है जो तिब्बत में स्थायी रूप से बस गए हैं और वहां काफी समय से रह रहे हैं, वहीं पले–बढ़े हैं।" तिब्बतियों को चिंता इस बात की है कि बहुत से तिब्बती इलाकों में व्यापक तौर पर मुख्यतः हान और कुछ दूसरे राष्ट्रीयताओं के लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, इससे मूल तिब्बती जनसंख्या हाशिए पर जा रही है और तिब्बत के नाजुक पर्यावरण को चुनौती मिल रही है। जनसंख्या की आवाजाही को नियंत्रित करने का प्रस्ताव चीनी संविधान और क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता के कानून के अनुच्छेद 43 के मुताबिक ही है जिसमें कहा गया है: "कानूनी प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय स्वायत्तशासी स्व–सरकार के अंग जनसंख्या की आवाजाही को नियंत्रित करने का उपाय कर सकते हैं।"

8. तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता से क्या तिब्बत में पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी?

जी हां, अपने नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तिब्बत एशिया की कई महान नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। आज तिब्बत के परंपरागत पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है। "पर्यावरण संरक्षण" और "प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल" को तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता पर ज्ञापन में पांचवीं और छठी बुनियादी जरूरत बताया गया है। तेजी से हो रहा सांस्कृतिक विलोपन, पर्यावरण विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन ऐसी मुख्य वजहें हैं जिससे सीटीए ने तिब्बती जनता के लिए वाजिब स्वायत्तता की मांग तेज कर दी है। हर साल इस बात के साक्ष्य बढ़ रहे हैं कि चीन की

पर्यावरण और विकास नीतियां गैर टिकाउ साबित हो रही हैं और इनसे पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान हो रहा है। इनमें उस नदी तंत्र पर बनने वाले बांध भी शामिल हैं जिनकी सहायक नदियां भारत, पाकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस तक पहुंचती हैं–इस तरह इससे दुनिया की करीब आधी जनसंख्या प्रभावित हो रही है।

9. सीटीए *मध्यम मार्ग नीति* पर आगे क्यों बढ़ रहा है और अभी तक इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं?

मध्यम मार्ग नीति को कई तरह से सफलता मिली है जिसमें तिब्बत के भीतर के तिब्बतियों से संपर्क और चीनी नेतृत्व के साथ हुई कई दौर की वार्ता शामिल है। इस नीति की वजह से ही मुख्यतः यह संभव हुआ है कि तिब्बत के मसले को न केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बल्कि चीनी लोगों से भी जबर्दस्त समर्थन मिला है। मध्यम मार्ग नीति की वजह से तिब्बती नेतृत्व और चीन सरकार के बीच वर्ष 1979 में सीधा संपर्क संभव हुआ जिसके बाद निर्वासित तिब्बतियों के चार तथ्यान्वेषी दल तिब्बत के भीतर गए और वहां की गहन यात्रा की। इन तथ्यान्वेषी प्रतिनिधिमंडलों ने यू–सांग के ल्हासा, शिगास्ते, ल्होखा, कोंगपो, साक्य, निंगत्री, ल्हुंत्से, सोना, सेथांग, ग्यांगत्से, छोखोरग्याल, सांगाछोलिंग, यारतोक और नाकर्तसे, आमदो के कानल्हो, सिलिंग, गोलोक, माल्हो, नाबा और जोएगे, खम के नांगछू, चामदो, देगे, कार्से, न्यारोंग, ग्यालथांग और मारखम जैसे तिब्बत के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। वर्ष 1982 और 1984 में चीनी नेता बीजिंग में वार्ता के लिए धर्मशाला से आए तथ्यान्वेषी प्रतिनिधिमंडल से मिले। वर्ष 2002 से 2010 के दौरान परमपावन दलाई लामा और चीनी नेतृत्व के प्रतिनिधिमंडल के बीच नौ दौर की औपचारिक वार्ता और एक अनौपचारिक मुलाकात संभव हुई। अब तक हजारों विद्यार्थी, भिक्षु और भिक्षुणी निर्वासन में जाकर अध्ययन कर पाए हैं और वे तिब्बती संस्कृति एवं धर्म के संरक्षण में योगदान कर रहे हैं।

मध्यम मार्ग नीति की वजह से ही कई सरकारों ने एक समाधान आधारित तिब्बत नीति का समर्थन किया है और उन्हें चीन के साथ अपनी वार्ताओं में तिब्बत की गंभीर और अत्यावश्यक समस्याओं को उठाने में मदद मिली है। इसे तिब्बत के भीतर के मौजूदा हालात के समाधान के लिए सबसे सक्षम विकल्प के रूप में सबसे प्रबल अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल हुआ है। कई राष्ट्रीय सरकारों ने मध्यम मार्ग नीति को आधिकारिक रूप से अपना समर्थन दिया है। इनमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। अकेले पिछले दो वर्षों में ही मध्यम मार्ग नीति को समर्थन देने के बारे में प्रस्ताव, संकल्प और बयान अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, ब्राजील़ और लक्जमबर्ग जैसी कई संसदों में पारित हुए हैं।

मध्यम मार्ग नीति को प्रभावी बनाने के लिए वार्ता का आह्वान करने वाले वैश्विक नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त नवी पिल्लई, विदेशी मामलों/सुरक्षा नीति पर यूरोपीय संघ की उच्च

प्रतिनिधि और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष लेडी कैथरीन एश्टन, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड और ताइवानी राष्ट्रपति मा यिंग जेआयू शामिल रहे हैं।

राष्ट्रपति बराक ओबामा की परमपावन दलाई लामा से 16 जुलाई 2011 और फिर 21 फरवरी 2014 को मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने "दलाई लामा की अहिंसा और मध्यम मार्ग नीति के अनुसरण में चीन के साथ संवाद की प्रतिबद्धता" की सराहना की और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि, "लंबे समय से जारी मतभेदों को दूर करने के लिए सीधे संवाद कायम करें।" व्हाइट हाउस ने कहा, "ऐसा संवाद जिसका कोइ नतीजा निकले चीन और तिब्बतियों, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा।"

मध्यम मार्ग नीति को हर साल चीनी समुदाय में भी समर्थन बढ़ता जा रहा है। चीन के कई सबसे सम्मानित बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने इस नीति का समर्थन किया है। इनमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैदी लिउ शियाओबो भी शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2008 में जारी उस खुले पत्र पर भी दस्तखत किया था जिसमें परमपावन दलाई लामा के शांति पहल को समर्थन दिया गया था। इसके बाद से चीनी विद्वानों और लेखकों द्वारा तिब्बत मसले को हल करने के लिए संवाद का समर्थन करने वाले 1,000 से ज्यादा लेख एवं विचार पेश किए गए हैं। इनमें बीजिंग के एक कानूनी एनजीओ, दि गोंगमेंग कॉन्सटिट्यूशनल इनीशिएटिव की एक रिपोर्ट शामिल है जिसमें तिब्बती जनता की समस्याओं का वर्णन करते हुए नीतियों की समीक्षा करने का आह्वान किया गया है।

वर्ष 2012 में 15 देशों में सक्रिय 82 चीनी एनजीओ ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, विभिन्न संसदों और सरकारों को एक याचिका भेजकर उनसे यह आग्रह किया कि "चीन सरकार से निवेदन करें कि वह जितनी जल्दी संभव हो वार्ता शुरू करे।" *मध्यम मार्ग नीति* का समर्थन करने वाले अन्य चीनी बुद्धिजीवियों में प्रख्यात लेखक वांग लिशियोंग, चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी से जुड़े और सांविधानिक विशेषज्ञ झांग बोशु, सिचुआन लिटररी पीरियॉडिकल के रान यनफेई, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और बीजिंग में रहने वाले कानूनी जानकार यू हाओछेंग, चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी के पूर्व अर्थशास्त्री सु शाओझी और कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव झाओ जियांग के करीबी सहयोगी यान जियाकी शामिल हैं।

मध्यम मार्ग नीति का बहुत से नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित हस्तियों ने भी समर्थन किया है जिनमें दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टुटु, अमेरिका के एली विजेल, अमेरिका के जोडी विलियम्स, लाइबेरिया के लेमाह गोवी, पोलैंड के लेक वालेसा, ईरान के शिरीन ईबादी, ग्वाटेमाला के रिगोबर्टा मेंछु, ईस्ट टिमोर के जोस रामोस होर्ता, अर्जेंटीना के अडोल्फो पेरेज एसक्विवेल, आयरलैंड के मैरीड कॉरिगन मैग्वायर और ब्रिटेन के बेट्टी विलियम्स शामिल हैं।

चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ को वर्ष 2012 में लिखे खुले पत्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं ने लिखा थाः "तिब्बत के लोगों की आकांक्षा सुनी जानी चाहिए। वे लंबे समय से सार्थक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने बातचीत और दोस्ताना मदद का रास्ता अख्तियार किया है। चीन सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और कोई अहिंसक समाधान निकालना चाहिए। इस तरह के समाधान की पेशकश हमारे मित्र और भाई परमपावन दलाई लामा ने की है जिन्होंने कभी भी अलग होने की बात नहीं की है और हमेशा एक शांतिपूर्ण रास्ता चुना है। हम चीन सरकार से यह प्रबल आग्रह करते हैं कि एक सार्थक वार्ता के लिए उनके द्वारा दिए जा रहे मौके का वह फायदा उठाए। एक बार इस संवाद माध्यम के बन जाने के बाद इसे खुला, सक्रिय और उत्पादक बनाए रखना चाहिए। इसके द्वारा उन मसलों का समाधान होना चाहिए जो मौजूदा तनाव की मूल हैं और इसमें तिब्बती जनता की गरिमा तथा चीन की अखंडता का सम्मान होना चाहिए।"